

मुश्किलों को  
अपनों के बीच  
रख दो या तो अपने  
रहेंगे या फिर मुश्किलें।  
- अज्ञात



## एनआरए के गठन को मंजूरी

अभी इस श्रेणी के तमाम पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया अलग-अलग एजेंसियां अपने-अपने ढंग से निपटाती हैं। इन सबकी परीक्षाएं अलग-अलग होती हैं, जिनका एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं होता।

अनिल शर्मा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह एजेंसी केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर बैंकों के नॉन गजेटेड पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता लाएगी। अभी इस श्रेणी के तमाम पदों पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया अलग-अलग एजेंसियां अपने-अपने ढंग से निपटाती हैं। इन सबकी परीक्षाएं अलग-अलग होती हैं, जिनका एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं होता।

ऐसे में नियुक्ति के इच्छुक युवाओं को इन सब पर नजर रखनी होती है और जिस भी एजेंसी की तरफ से भर्ती की सूचना आए, उसके मुताबिक फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जाहिर है, इसमें उनके

पैसे की ही नहीं ऊर्जा की भी बर्बादी होती है। नई व्यवस्था में एनआरए फिलहाल स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (एसएसी), इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तमाम भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) आयोजित करेगी और उसके आधार पर योग्य प्रत्याशियों को शॉर्टलिस्ट करके उनके नाम इन एजेंसियों को भेज देगी। इसके बाद संबंधित एजेंसियां एक स्तर तक अपनी क्षमता सिद्ध कर चुके इन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगी।

सीईटी स्कोरिंग तीन साल तक प्रभावी रहेगी और इसमें बैठने की कोई सीमा नहीं रखी गई है। मतलब यह कि जब तक उम्र है, तब तक कोई भी युवा चाहे जितनी बार भी सीईटी में बैठ सकता है। बहरहाल,

अभी एनआरए गठन की प्रक्रिया शुरुआती स्तर में ही है और इससे संबंधित सारे प्रावधान अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं। फिर भी एक बात साफ है कि यह नई व्यवस्था नियुक्ति की प्रक्रिया की लंबाई को किसी रूप में कम नहीं करती, बल्कि इसमें एक परीक्षा और जोड़ देती है।

अलबत्ता इससे यह फायदा जरूर होगा कि भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने वाले मौजूदा तंत्र पर दबाव कम होगा। अभी चाहें बैंकों की नियुक्तियां हों या रेलवे और एसएससी की, एक-डेढ़ हजार पदों के लिए भी लाखों की संख्या में आवेदन आ जाते हैं। हर एजेंसी को आवेदकों की इस भीड़ से अलग-अलग निपटना पड़ता है। सीईटी के जरिए

प्राथमिक स्तर का फिल्टर लगेगा, जिसके बाद सीमित संख्या में ही प्रत्याशी मुख्य परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे, जिनके बीच से योग्य उम्मीदवारों का चयन ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन खतरा यह है कि भर्ती एजेंसियों का दबाव कम करने की यह कवायद कहीं देश की नई पीढ़ी पर दबाव और ज्यादा बढ़ा न दे। हमें इस मोर्चे पर विशेष सावधानी रखते हुए ऐसे सचेत प्रयास करते रहने होंगे, जिससे सीईटी में सफल न हो पाने वाले युवा भी तनावग्रस्त न हों। एक बड़ा सवाल आरक्षण की व्यवस्था से जुड़ा है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि सीईटी में आरक्षण की व्यवस्था को किस रूप में लागू किया जाएगा। उम्मीद करें कि टेस्ट के ब्यौरे सामने आने के साथ ही इस विषय में भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

## सहिष्णुता

अशोक वोहरा। अंतरात्मा की आवाज पर दल बदलने वाले लोग, 'अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने से टिका दिया' जैसी लाइन लिखने के लिए परसाईजी को सबक सिखाने का निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दे चुके होते। परसाई कहते थे, 'मैं सुधार के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए लिखता हूँ। वे यह भी मानते थे कि सिर्फ लेखन से क्रांति नहीं होती। हां, उसकी भावभूमि जरूर बन सकती है।' वे कहते थे कि मुक्ति कभी अकेले की नहीं होती। नौजवानों को संबोधित करते हुए वे लिखते हैं, 'मेरे बाद की और उसके भी बाद की ताजा, ओजस्वी, तरुण पीढ़ी से भी मेरे संबंध हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि अपने बुजुर्गों की तरह अपनी दुनिया छोटी मत करो। मत भूलो कि इन बुजुर्ग साहित्यकारों में से अनेक ने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे वर्ष जेल में गुजारे।

धर्म-दर्शन



## संपादकीय

### पहचान को प्रतिनिधित्व

गौर करने की बात यह है कि लोगों का असंतोष पिछले तीन दशक से लागू इस शासन पद्धति से भी है, जिसमें शासक अपने नीतिगत और प्रशासनिक दिवालियापन को बड़ी आसानी से अपनी धार्मिक राजनीति के पीछे छिपा ले जाते हैं। इस तरह लेबनान अपने अनुभव से जो संदेश दे रहा है, उसमें दो तत्व साफ देखे जा सकते हैं। विरोध प्रदर्शन अब भी जारी हैं। कोई नहीं जानता कि नई व्यवस्था क्या होगी, हसन दियाब की जगह कौन प्रधानमंत्री पद कौन संभालेगा। जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह लोगों की समस्याएं हल करेगा, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं है। उनकी समस्याएं कैसे हल होंगी, इसका भी कोई अंदाजा उन्हें नहीं है। वे बस यह चाहते हैं कि उनके देश का नेतृत्व उनकी समस्याएं हल करे। यह विचित्र स्थिति ही इतिहास के इस मोड़ पर लेबनान को खास बनाती है। लोकतंत्र में जनता की उदासीनता को तमाम समस्याओं की जड़ और उसकी जागरूकता को इनका हल माना जाता है। कहते हैं, जनता जाग जाए तो क्या नहीं हो सकता। पर लेबनान की जनता तो जागी हुई है। एक तो यह कि जनता का जागकर सड़क पर उतर आना सकारात्मक बदलाव के लिए काफी नहीं होता। और दूसरी बात यह कि पहचान को प्रतिनिधित्व देना राजनीतिक रूप से भले दुरुस्त हो, पर जरूरी नहीं कि इससे संबंधित समाज की समस्याओं का समाधान भी निकल आए।

कभी सोवियत संघ जैसा महाबली देश टुकड़ों में बिखर कर इतिहास के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ता है तो कभी नेपाल जैसा छोटा देश 'मुक्ति युद्ध' की कामयाबी से उस संदेश पर पुनर्विचार की जरूरत जता देता है।

## जंगल की आग

प्रणव प्रियदर्शी ।।

लेबनान बहुत छोटा सा देश है। करीब 70 लाख आबादी और साढ़े दस हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। मगर मानव समाज की उतार-चढ़ाव भरी यात्रा में इतिहास के किस मोड़ पर कौन सा महत्वपूर्ण संदेश कहां से आ जाएगा, कहा नहीं जा सकता। कभी सोवियत संघ जैसा महाबली देश टुकड़ों में बिखर कर इतिहास के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ता है तो कभी नेपाल जैसा छोटा देश 'मुक्ति युद्ध' की कामयाबी से उस संदेश पर पुनर्विचार की जरूरत जता देता है। पश्चिम एशियाई मुक्त लेबनान कोई एक साल से जिस उथल-पुथल से गुजर रहा है वह सामान्य नहीं है। इस बीच यहां लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन होते रहे, हालांकि कोई निश्चित नेतृत्व इसके पीछे नहीं है। सिविल सोसाइटी की पहचान के साथ कई व्यक्ति और संगठन इसमें शामिल हैं, पर मूलतः यह एक जन आंदोलन है जो इस पूरी अवधि में लगभग शांतिपूर्ण रहा है। इसकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरान यहां दो प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है।

स्थानीय तौर पर इस आंदोलन को 'अक्टूबर क्रांति' का नाम दिया गया है क्योंकि विरोध प्रदर्शनों के इस सिलसिले की शुरुआत 17



अक्टूबर से हुई, जो दुनिया भर में रूस की समाजवादी क्रांति की तारीख के रूप में जाना जाता है। इसकी तात्कालिक वजह लेबनान के जंगलों में आग की करीब 100 घटनाएं बनीं जिनसे न केवल सैकड़ों लोग विस्थापित हुए बल्कि बड़े पैमाने पर हरियाली भी नष्ट हुई। लेबनानी लोग अपनी हरियाली पर गर्व करते रहे हैं। सरकार जंगल की आग पर काबू पाने की खास कोशिश करती नहीं दिखी, जिससे लोगों ने खुद को आहत महसूस किया। फिर भी यह तात्कालिक कारण ही था। महंगाई और बेरोजगारी लोगों के सन्न का पहले से इम्तहान ले रही थी। तेल और रोटी की कीमतें आसमान छू रही थीं। अगस्त में आम बेरोजगारी स्तर 25 फीसदी और युवा बेरोजगारी स्तर 37 फीसदी था। इसमें बिजली-पानी की किल्लत भी जोड़ लीजिए। लेबनान में आठ घंटे रोज की पावर राशनिंग

आम है। 24 घंटे बिजली की सुविधा 'जेनरेटर माफिया' के सहयोग से ही हासिल होती है जिसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पीने का पानी भी बोटलों में ही मिल पाता है जो निजी कंपनियां बेचती हैं। ये सारे मुद्दे सरकार के नाकारेपन के प्रमाण के रूप में लोगों के सामने थे। बरसों से जमा गुस्सा इन सरकार विरोधी प्रदर्शनों में निकल रहा था। देखते-देखते विरोध प्रदर्शनों ने इतना तीखा रूप ले लिया कि सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री साद हरीरी को इस्तीफे की घोषणा करनी पड़ी। शिक्षा मंत्री हसन दियाब को उनकी जगह प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन इससे न तो हालात में कोई बदलाव आया, न ही लोगों को ऐसी कोई उम्मीद नजर आई। सो विरोध प्रदर्शन भी जारी रहे। लोगों का असंतोष बना रहा। उसका लोकतांत्रिक ढंग से इजहार होता रहा। पुलिस चौकसी, बंदोबस्त और गिरफ्तारी का अपना काम करती रही।

इस सबके बीच ही अगस्त के पहले सप्ताह में राजधानी बेरुत के बंदरगाह में हुए दो भीषण विस्फोटों ने न सिर्फ लेबनान बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी तंत्र की लापरवाही को रेखांकित किया। पता चला, करीब ढाई हजार टन विस्फोटक पदार्थ वहीं एक गोदाम में बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के छह साल से पड़ा हुआ था और उसी इमारत में पटाखों का स्टॉक भी रख दिया गया था।

सूटिकू बवाल-5453		****			
4	6	3	8	9	7
1	9	6	5	4	
4	5		8		
2	5	4	6	1	
3		1	7		
	3				
5	9	7	2	6	
7	6	4	3	9	2

सूटिकू बवाल-5452 का हल	
प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भर जाने आवश्यक हैं।	5 7 2 3 8 4 1 9 6
प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।	8 6 1 9 2 5 7 3 4
वहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।	3 9 4 1 6 7 5 8 2
पंक्तियों का केवल एक ही हल है।	2 5 7 4 1 3 8 6 9
	4 8 6 5 9 2 3 7 1
	1 3 9 6 7 8 4 2 5
	6 2 3 7 4 1 9 5 8
	9 4 5 8 3 6 2 1 7
	7 1 8 2 5 9 6 4 3

## अपना ब्लॉग

समाज का  
संवैधानिक समर्थन

मोहन। पहले दुर्घटनावश पटाखों में आग लगी, फिर गोदाम में पड़े अमोनियम नाइट्रेट ने कसर पूरी कर दी। इसकी उतनी ही विस्फोटक प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। विरोध प्रदर्शन का नया दौर शुरु हुआ। नतीजा यह कि नए प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफे की घोषणा कर दी। जनवरी में आए हसन दियाब अब कामचलाऊ प्रधानमंत्री हैं और नई व्यवस्था होने तक इस पद की जिम्मेदारी देख रहे हैं। वह न केवल अपनी समस्याओं को समझ रही है बल्कि उनके हल के लिए सड़क पर उतरकर निरंतर आवाज उठा रही है, जेल जा रही है, लाठी खा रही है। फिर भी समाज किसी तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। आखिर क्यों? जवाब की तलाश शुरु करने से पहले लेबनान को खास बनाने वाले एक और महत्वपूर्ण फ़ैक्टर पर गौर कर लेना जरूरी है। वह है वहां के शासन का सेक्टरियन स्वरूप। वहां राष्ट्रपति हमेशा ईसाई, प्रधानमंत्री सुन्नी और संसद अध्यक्ष शिया समुदाय के होते हैं।

कोटोवा में लाइली लक्ष्मी योजना में कमी

कौन कम बस्त कहता है कमी आई है हमेशा मेरे कंधों पर रहती है...

